POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2024-26 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2025/अंक 12

मासिक प्रेषण दि. 8 दिसम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस, जयपुर

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 दिसम्बर, 2025 मूल्य 50 पैसे

बाबूलाल कांकरेलिया 'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते रहे हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है।

इस बार वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार 'कट्स' द्वारा अजमेर में 'मोटिवेशन एण्ड इम्पेक्ट ऑफ ग्राससूट फिलांथ्रोपी इन राजस्थान' परियोजना के तहत आयोजित हितधारक परामर्श बैठक के दौरान जयपुर जिले के भानपुर कलां गांव के मूल निवासी स्वतंत्र पत्रकार बाबूलाल कांकरेलिया को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर सम्मानित किया गया। कांकरेलिया ने वर्ष 2024 के दौरान 'सेहत पर भारी पैकेट बंद खाद्य पदार्थ एवं प्रोसेस्ड फूड' विषय पर विभिन्न समाचारपत्रों में कई रोचक स्टोरियां प्रकाशित कर आमजन में जागरूकता लाने एवं जनचेतना जागृत करने का काम किया है।

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! देश में हर साल पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तभी से यह दिवस भारतीय राजनीति और जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस बन गया है।

भारत के सच्चे सपूत व अनंत प्रतिभाओं के धनी थे अटलजी। सरल, निर्मल और स्वच्छन्द स्वभाव उनकी खासियत थी....। वर्ष 1983 में पहली बार मुझे अटलजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 'ग्राम गदर' भित्तीपत्र का पहला अंक लेकर मैं उनके पास गया था। उन्होंने बड़ी तल्लीनता से 'ग्राम गदर' को पढ़ा था।

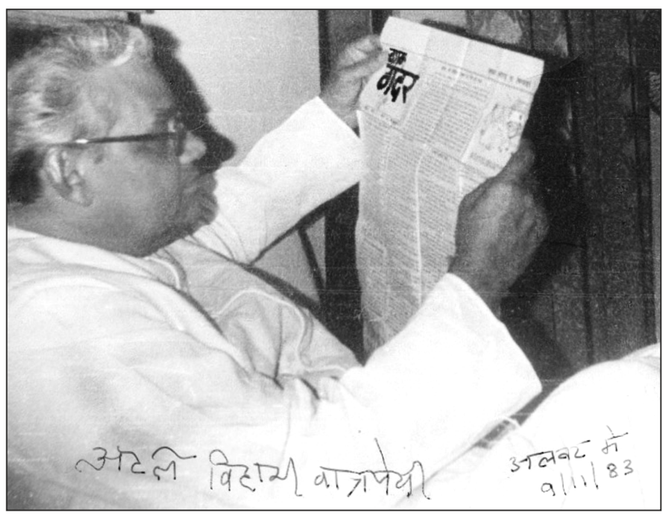

उन्होंने पूछा तो मैंने बताया था, राजस्थान के दूर दराज के गांवों तक समाचार-पत्र नहीं पहुंचते। इससे गांव के लोगों को उनके लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती। जिससे वे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। डाक विभाग के ई.डी. कर्मचारी (अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी) स्वेच्छा से गांव की चौपाल पर इसे चिपकाते हैं और पढ़े-लिखे गांव के लोग इसे पढ़कर सुनाते हैं। गांव वाले इससे जागरूक होंगे।

यह सब सुनकर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा था 'सवालिया समाज का गठन इसका खास मकसद होना चाहिए... यह नेक काम है, इससे शासन-प्रशासन में सुशासन आएगा।' उन्होंने जोर देकर कहा था 'नागरिकों में सवाल खड़ा करने की क्षमता होगी तो प्रशासनिक ढांचे में सुधार आएगा, जवाबदेही होगी, पारदर्शिता आएगी जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सकेगा।'

उनका दिया यह मंत्र आज भी मेरे मन-मस्तिष्क में समाया हुआ है। प्रयास भी रहता है, 'ग्राम गदर' में ऐसी खबरें छपें जिनसे सरकार में निरंतर सुधार की प्रक्रिया सिर्फ कागज पर नहीं धरातल स्तर पर क्रियान्वित होती दिखे। इसके लिए प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली में सुधार लाना बेहद जरूरी है। इसी से सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेहिता जुड़ी है....।

मोदी सरकार का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी तभी साकार हो सकेगा जब खेती-किसानी, बेरोजगारी, औद्योगिक विकास, महंगाई एवं भ्रष्टाचार जैसी अनेक चुनौतियों से निपटने में प्रशासन चुस्त और दुरुस्त होगा।

भारत में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और यह निरंतर प्रगति करे, इसके लिए केंद्र सरकार कई नीतिगत कदम उठा रही है। जिनसे युवाओं के लिए भी अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से कहा कि वे इन अवसरों का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के साथ ही युवाओं के प्रशिक्षण के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि युवा उनका भरपूर उपयोग कर सके। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा से कमाए धन को वंचित वर्ग और देश की सेवा में भी लगाना चाहिए। विद्यादान सबसे श्रेष्ठ दान है। इससे जीवनभर परम संतुष्टि मिलती है।

रिसर्च-इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा

हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख करोड़ रुपए के रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन (आरडीआई) फंड की शुरुआत की है। इस फंड से उच्च स्तर की तकनीकी और जोखिम वाले क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग देश के वैज्ञानिकों की क्षमताओं को बेहतर करने के लिए होगा। देश में अनुसंधान और नवाचार के लिए माहौल तैयार किया जाएगा। इक्कीसवीं सदी में दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ आकर विज्ञान, तकनीक और नवाचार पर मंथन करने और मिलकर दिशा दिखाने की जरूरत है। आरडीआई कोष का पैसा नए मौके खोलने के लिए है। इसका सीधा असर देश में बनने वाले उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ेगा।

महिलाओं में बढ़ेगा उद्यमिता कौशल

महिलाओं में उद्यमिकता कौशल को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना काफी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। योजना में महिलाओं को उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित उद्यमों सहित कई क्षेत्रों में ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

योजना के तहत व्यक्तिगत महिला उद्यमियों व महिला स्वयं सहायता समूहों को 50 लाख रुपए तक

और महिला स्वयं सहायता समूह कलस्टर और फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण किफायती दरों पर मिलता है। साथ ही, ऋण राशि का 25 फीसदी अनुदान के रूप में दिया जाता है। योजना में वंचित वर्ग की महिलाओं को 30 फीसदी तक अनुदान देने का प्रावधान है।

देश में नई कृषि क्रांति की तैयारी

नीति आयोग ने देश में खेती की दिशा और दशा बदलने के लिए अगले पांच साल के लिए नया रोडमैप तैयार किया है। इसमें कृषि में 100 फीसदी आत्मनिर्भरता लाने के लिए ऐसी तकनीकों को चुना गया है, जिसके जरिए देश की कृषि में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।

चुनी गई ये तकनीकें जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, मिट्टी की थकान और बाजार की अनिश्चितता को खत्म करने में मददगार बनेगी। रोडमेप पर प्रभावी अमल से देश में कृषि लागत 40 प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब खेती ड्रोन, एआइ और बीजों की जीन एडिटिंग से होगी। पानी की बरबादी शून्य होगी और पैदावार भरपूर हो सकेगी। इससे किसान की आय बढ़ेगी।

गांवों की बनेगी स्वास्थ्य कुंडली

प्रदेश में सरकार गांवों की सेहत सुधारने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना ला रही है। इस योजना में उन गांवों को चुना जा रहा है, जहां बीमारी के आंकड़े और इलाज का खर्च ज्यादा है।

पहले चरण में हर जिले की पांच ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन उनमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित होना चाहिए। इन पंचायतों में 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक औषधि 'स्वर्ण प्राशन' दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व व बाद में औषधि युक्त लड्डू दिए जाएंगे। जो गांव 18 स्वास्थ्य सूचकांकों में खरा उतरेगा, उसे आदर्श ग्राम का तमगा दिया जाएगा।

किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा

केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना 'पीएम किसान सम्मान निधि' में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन ट्रेकिंग और सत्यापन में पता चला है कि देश में 31.01 लाख संदिग्ध लाभार्थी लंबे समय से योजना का गलत फायदा उठा रहे थे। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।

केंद्र सरकार अब तक ऐसे लोगों से 416 करोड़ रुपए की वसूली कर चुकी है। सभी राज्यों में भी वसूली की प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों को संदिग्ध लाभार्थियों के नाम हटाने, नोटिस भेजने तथा फंड रिकवरी के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में सत्यापन शुरू कर दिया गया है। गलत लाभार्थियों से वसूली कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

राजस्थान बनेगा फूडबास्केट...

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही विकसित राजस्थान-2047 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। विजन डॉक्यूमेंट में हर गांव तक पानी पहुंचाने, बंजर जमीन का टैग हटाकर देश में प्रदेश को फूड बास्केट बनाने के साथ, हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर राजस्थान को अग्रणी बनाने का रोडमैप है।

विजन डॉक्यूमेंट में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन, पर्यावरण और ग्रामीण व शहरी विकास पर खास नजर रखते हुए बताया गया है कि राजस्थान इस तरह से विकसित होगा। यह सब भले ही सपने जैसा लगे, लेकिन सरकार का दावा है कि प्रदेश को हर क्षेत्र में विकसित एवं अग्रणी बनाया जाएगा। कार्यों में रफ्तार धीमी नहीं पड़े, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी है।

प्रदेश में शुरू होगा 'रोजगार उत्सव'

प्रदेश में दिसंबर माह में 'रोजगार उत्सव' आयोजित कर 20 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबंधित अधिकारियों से सभी लंबित भर्तियों को शीघ्र निस्तारित कर पात्र अभ्यर्थियों को जल्द नौकरी देने के लिए कहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर योग्य युवा को सम्मानजनक रोजगार मिले, ताकि उसकी ऊर्जा प्रदेश के निर्माण में लग सके। दिसंबर में राज्यभर में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों में विभिन्न विभागों की चयन प्रक्रियाएं पूरी कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र पदान किए जाएंगे। दिसंबर की 20 हजार नियुक्ति मिलाकर अब तक 1.12 लाख युवाओं को नियुक्तियां मिल जाएंगी।

सहकार से समृद्धि की संकल्पना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने में राजस्थान अग्रणी राज्यों में है। राज्य सरकार सहकारी समितियों को सशक्त कर ग्रामीणों की आय बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा किसानों को बेहतर बाजार के अवसर सुनिश्चित कर रही है।

उन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नवीन को-ऑपरेटिव अधिनियम से सहकारिता आंदोलन अधिक समावेशी बनेगा। इससे जवाबदेहिता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नवीन को-ऑपरेटिव कोड में वे सभी प्रावधान जोड़े जाएं, जिससे सहकारी समितियों को पारदर्शी, आर्थिक रूप से मजबूत एवं सभी के लिए सुलभ बनाया जा सके।

टोक्यो में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदीप महता देंगे व्याख्यान

जापान के टोक्यो स्थित कोनराड एडेनॉयर स्टिफ्टंग (केएएस) ने 'कट्स इंटरनेशनल' के महामंत्री प्रदीप एस. महता को अमेरिकी व्यापार नीति एवं विश्व आर्थिक व्यवस्था से जुडे मुद्दों पर व्याख्यान देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में आमंत्रित किया है।

महता 2 से 5 दिसंबर तक टोक्यो में आयोजित होने वाले सम्मेलन में विशेष रूप से एशिया-प्रशांत व्यापार ढांचे पर व्याख्यान देंगे। सम्मेलन के दूसरे सत्र में विश्व व्यापार संगठन के भविष्य पर भी विचार प्रस्तुत करेंगे। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में विश्वभर से 60 से अधिक विशेषज्ञ एवं नीति निर्माता भाग लेंगे।

उर्वरक कम तोला, विक्रेता और कंपनी को देना होगा हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय में किसान प्रदीप कुमार चौधरी ने वकील के मार्फत अपने गांव की दुकान ईको ट्रेडिंग कंपनी एवं उर्वरक उत्पादक कंपनी के खिलाफ 21 जून 2024 को परिवाद दर्ज कराया। मामले के अनुसार किसान प्रदीप कुमार चौधरी ने इको ट्रेडिंग कंपनी से भारतीय किसान जन

उर्वरक शक्ति एनपी के 50 किलो के तीन बैग खरीदे थे। प्रत्येक बैग की कीमत 1,470 रुपए थी। लेकिन प्रत्येक बैग में 50 किलो उर्वरक की बजाय केवल 46 किलो उर्वरक ही निकला। इससे विक्रेता द्वारा उनसे 353 रुपए अधिक लिए गए।

मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रत्येक बैग में 50 किलो के उर्वरक की जगह 46 किलो देकर पूरी कीमत वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और सेवा दोष माना। आयोग ने विक्रेता और कंपनी पर 85 हजार रुपए का हर्जाना लगाया साथ ही किसान प्रदीपकुमार चौधरी को अधिक वसूली गई राशि 353 रुपए ब्याज सहित वापस देने का आदेश दिया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट 'कट्स' जयपुर